JHANDEWALAS
FOODS LIMITED

125 YEARS

0141-2703308
info@namans.co.in
www.namans.co.in

Date: 03 August 2024

To,
The General Manager
Department of Corporate Services
BSE LTD-SME Platform
Phirozejeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai: 400001

Scrip Code: 540850
Scrip Name: JFL

Subject: Newspaper Publication – Notice of AGM

Dear Sir/Ma'am,

With respect to captioned subject, please find enclosed copy of newspaper publication with respect to notice of 18th Annual General Meeting of the Company that is scheduled on Wednesday, 28 August 2024. The aforesaid notice has been published on Saturday, 03 August 2024 in following newspapers:

a) Nafa Nuksan (Hindi Edition) and
b) The Economic Times (English Edition).

This is for your information and record.

Thanking you,

For Jhandewalas Foods Limited

Raakesh B Kulwal
Digitally signed by Raakesh B Kulwal
Date: 2024.08.03 13:06:19 +05'30'

Raakesh B Kulwal
Managing Director
DIN: 00615150

ऑनलाइन शॉपिंग से मिल रहा है लॉजिस्टिक्स कम्पनियों के बिजनेस को सपोर्ट

नई दिल्ली@एजेंसी

देश के छोटे शहरों में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है। इससे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का कारोबारी आंकड़ा भी बढ़ रहा है। गत करीब एक दशक से हमने इस श्रेणी को बढ़ते हुए देखा है। आज चर्चा इस बात को लेकर है कि ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने का लाभ केवल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को ही इससे लाभ नहीं हो रहा है बल्कि लॉजिस्टिक्स कम्पनियों को भी इससे बढ़त मिल रही है। लॉजिस्टिक्स यूनीकॉर्न ईकॉम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड और एक्सप्रेसबीज(बिजीबीज लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड), डिलीवरी स्टार्टअप्स जैसे शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, डेलीवरी, शिपरॉकेट को टीयर टू शहरों से रेवेन्यू में अच्छी हिस्सेदारी प्राप्त हो रही है।

देश का ई-कॉमर्स मार्केट वर्ष 2030 तक तीन सौ बिलियन डॉलर तक वृद्धि करने की सम्भावना रख रहा है। रेडसीर कन्सल्टेंट्स की अक्टूबर रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। इसमें से ज्यादा ग्रोथ टीयर टू सिटीज से आयेगी, जहां पर लोग ई-कॉमर्स को अपना रहे हैं। इन्वेस्टकॉर्प के पार्टनर के अनुसार साठ प्रतिशत से ज्यादा ग्रोथ स्मॉल टाउंस से आ रही है। ऐसे में यहां पर लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी होगी। गौरतलब है कि इन्वेस्टकॉर्प एक्सप्रेसबीज में निवेशक भी है। 2020 में निवेश के बाद एक्सप्रेसबीज का पिन कोड नम्बर दोगुना हो गया। वह टॉप दस शहरों के अलावा अन्य शहरों से आधे से ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त कर रही है। देश में एक्सप्रेसबीज का वितरण नेटवर्क काफी बेहतर है।

दूसरा उदाहरण ईकॉमएक्सप्रेस है, जिसे टीयर टू मार्केट्स आदि से 65 प्रतिशत पार्सल वॉल्यूम प्राप्त हो रहा है। उसे दो प्रकार के कन्ज्यूमर्स मिल रहे हैं। पहले वे जो वैल्यू कॉन्शियस हैं। ये वे लोग हैं जो सोशियल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से परिधान या जूते खरीदते हैं। दूसरे ब्राण्ड कॉन्शियस कन्ज्यूमर्स हैं जो लार्ज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं। टीयर टू मार्केट्स या अन्य में डिलीवरी करने के लिये दो चीजों पर ध्यान देना होता है। पहला स्पीड और दूसरा क्वालिटी। चीजों के टूटने-फूटने या डिफेक्टिव चीजों की बात तो यह हर मार्केट के लिए है लेकिन टीयर टू आदि शहरों में स्पीड और एक्यूरेट डिलीवरी भी अहम है। ऐसे में लॉजिस्टिक्स फर्म्स के लिए यह फोकस एरिया रहता है।

इंडस्ट्री एक्जीक्यूटिव्ज के अनुसार इन शहरों में 75 प्रतिशत ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स कैश डिलीवरी पर लिये जाते हैं। ऐसे में यदि प्रोडक्ट पहुंचने में देरी हुई तो वह असेप्ट होगा या नहीं, इस पर संचय रहता है। शिपरॉकेट के सीईओ के अनुसार विद एवरी पासिंग डे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर के ड्राप होने की सम्भावना करीब सात प्रतिशत होती है। कुल मिलाकर हम यह कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में छोटे शहरों की हिस्सेदारी बढ़ने का पॉजिटिव असर लॉजिस्टिक्स कम्पनियों को लाभ दे रहा है।

ब्रीफ न्यूज

2024-25 में डेयरी इंडस्ट्री की रेवेन्यू बढ़ेगी 13-14 प्रतिशत

मुंबई@पीटीआई। भारत के डेयरी उद्योग को चालू वित्त वर्ष में 13-14 प्रतिशत की स्वस्थ राजस्व वृद्धि देखने को मिलेगी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उपभोक्ता मांग के साथ-साथ कच्चे दूध की बेहतर आपूर्ति जारी है, जिससे डेयरी उद्योग बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। क्रिसिल रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि जहां मूल्य वर्धित उत्पादों (वीएपी) की बढ़ती खपत से मांग को समर्थन मिलेगा, वहीं अच्छे मानसून की संभावनाओं से पर्याप्त दूध की आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे दूध की आपूर्ति में वृद्धि से डेयरी कंपनियों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ेगी। हालांकि, अगले दो वित्त वर्षों में संगठित डेयरियों द्वारा जारी पूंजीगत व्यय के कारण ऋण का स्तर बढ़ेगा, लेकिन मजबूत बही-खाते की वजह से चीजें स्थिर रहेंगी। क्रिसिल ने रिपोर्ट में कहा है कि दूध खरीद की स्थिर कीमतें डेयरियों की लाभप्रदता के लिए शुभ संकेत हैं। इस वित्त वर्ष में उनकी परिचालन लाभप्रदता में 0.40 प्रतिशत का सुधार होने की उम्मीद है और यह छह प्रतिशत पर पहुंच जाएगी।

आईटीसी का जून तिमाही का शुद्ध लाभ मामूली गिरावट के साथ 5,177 करोड़

नई दिल्ली@एजेंसी। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत आईटीसी लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में मामूली घटकर 5,176.99 करोड़ रुपये रहा है। आईटीसी लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसके मुनाफे पर व्यापक आर्थिक चुनौतियों का असर पड़ा है। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 5,189.61 करोड़ रुपये रहा था। आईटीसी लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसकी परिचालन आय जून तिमाही में 7.45 प्रतिशत बढ़कर 20,029.60 करोड़ रुपये रही है। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 18,639.48 करोड़ रुपये थी। आईटीसी का कुल खर्च जून तिमाही में 11.02 प्रतिशत बढ़कर 13,791.01 करोड़ रुपये रहा है। आईटीसी की कुल आमदनी (अन्य आय मिलाकर) बीते वित्त वर्ष की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में 7.03 प्रतिशत बढ़कर 20,724.48 करोड़ रुपये थी।

टाटा प्ले ने अपने पैक से सोनी नेटवर्क के चैनल हटाने शुरू किए

नई दिल्ली@एजेंसी। डीटीएच सेवा प्रदाता टाटा प्ले ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के चैनलों को कम दर्शक संख्या का हवाला देते हुए अपने पैक से हटाना शुरू कर दिया है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया (एसपीएनआई) ने इस कदम का विरोध करते हुए इसे 'मनमाना' निर्णय बताया है। टाटा प्ले (पहले टाटा स्काई) ने अपने अलग-अलग चैनल पैक से एसपीएनआई के चैनलों को हटाना शुरू कर दिया है। इनमें कम देखे जाने वाले चैनलों को हटाया जा रहा है और उसी के हिसाब से मासिक शुल्क समायोजित किया जा रहा है। इस घटनाक्रम पर टाटा प्ले के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हरित नागपाल ने कहा कि मंच कम देखे जाने वाले चैनलों को हटाकर चैनल पैक को सुव्यवस्थित कर रहा है और उसी के हिसाब से मासिक शुल्क समायोजित कर रहा है। इस बीच एसपीएनआई ने बयान में इसे एक आश्चर्यजनक निर्णय बताते हुए कहा कि टाटा प्ले का 'दर्शकों की संख्या में कमी' का कथानक भ्रामक है। एसपीएनआई ने अंदेशा जताया कि यह मनमाना निर्णय उसे कोई सूचना दिए बिना या उनके ग्राहकों की प्राथमिकताओं पर विचार किए बिना लिया गया है।

जून में चाय का उत्पादन घटकर 14.23 करोड़ किलोग्राम पर

कोलकाता@एजेंसी। जून महीने में चाय का उत्पादन घटकर 14 करोड़ 23.9 लाख किलोग्राम रह गया है। पिछले साल की समान अवधि में चाय का उत्पादन 14 करोड़ 51.6 लाख किलोग्राम का हुआ था। चाय बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जून में उत्तर भारत के बागानों में उत्पादन मामूली रूप से बढ़कर 11 करोड़ 75.6 लाख किलोग्राम हो गया, जबकि पिछली समान अवधि में यह 11 करोड़ 67.8 लाख किलोग्राम का हुआ था। आंकड़ों के अनुसार, जून के दौरान दक्षिण भारत में उत्पादन घटकर दो करोड़ 48.3 लाख किलोग्राम रह गया, जबकि वर्ष 2023 के इसी महीने में यह दो करोड़ 83.8 लाख किलोग्राम था। जून, 2024 में पश्चिम बंगाल में उत्पादन वर्ष 2023 के इसी महीने के चार करोड़ 66.5 लाख किलोग्राम से तेजी से घटकर 4.005 करोड़ किलोग्राम रह गया। हालांकि, असम में उत्पादन जून, 2024 में पिछले इसी महीने के छह करोड़ 65.1 लाख किलोग्राम से बढ़कर सात करोड़ 34.8 लाख किलोग्राम हो गया। जून, 2024 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर संगठित कंपनियों (बड़ी फैक्ट्रियों) का उत्पादन छह करोड़ 66.5 लाख किलोग्राम रहा, जबकि छोटे चाय उत्पादकों का उत्पादन महीने के दौरान सात करोड़ 57.4 लाख किलोग्राम रहा। सीटीसी किस्म का उत्पादन 12 करोड़ 62.9 लाख किलोग्राम रहा, इसके बाद एक करोड़ 41.5 लाख किलोग्राम ऑर्थोडॉक्स का और 19.5 लाख किलोग्राम ग्रीन टी का उत्पादन हुआ।

Data Insights

A world of Feminists? Far from it...

India and Spain are the only countries where more than 50% respondents identify themselves as Feminist

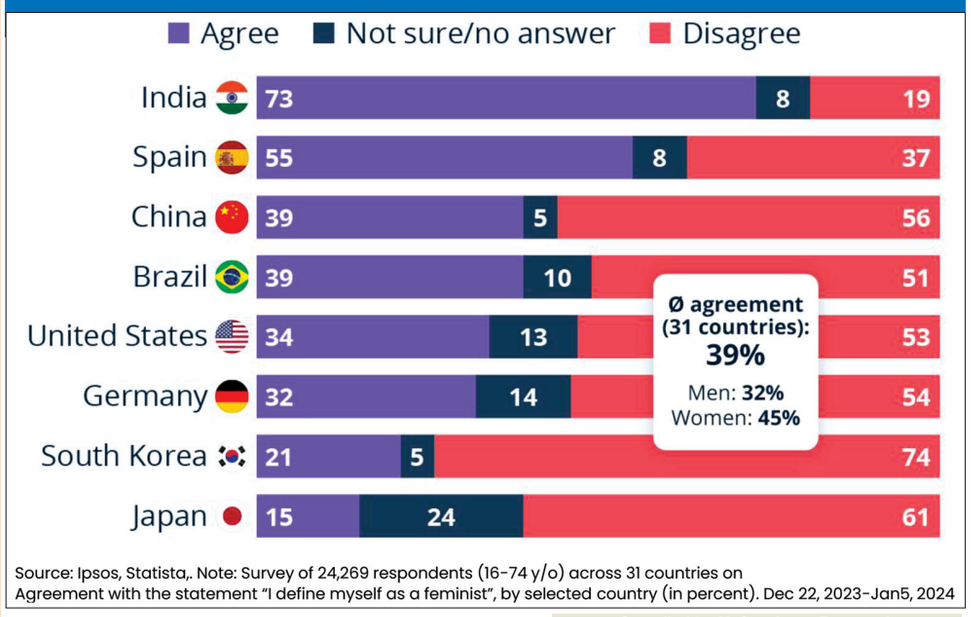

Source: Ipsos, Statista,. Note: Survey of 24,269 respondents (16-74 y/o) across 31 countries on Agreement with the statement "I define myself as a feminist", by selected country (in percent). Dec 22, 2023-Jan5, 2024

Compiled by **Nafanuksan Research**

मोबाइल कनेक्शन चाहने वाले फॉरेनर्स के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन अब ऑप्शनल

नई दिल्ली@एजेंसी

सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए भारत यात्रा के दौरान मोबाइल कनेक्शन को लेकर नियमों में ढील दी है। इसके लिए स्थानीय नंबर पर एकबारगी पासवर्ड भेजने के प्रावधान को वैकल्पिक बनाया गया है।

दूरसंचार विभाग ने 31 जुलाई को एक आदेश में कहा कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण वे वैकल्पिक नंबर उपलब्ध नहीं करा पाते। इसका उपयोग मौजूदा डिजिटल केवाईसी (डी-केवाईसी) प्रक्रिया के तहत हस्ताक्षर के रूप में ओटीपी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

विभाग ने आदेश में कहा कि मोबाइल कनेक्शन चाहने वाले विदेशी नागरिक के लिए एकबारगी पासवर्ड (ओटीपी) को लेकर वैकल्पिक मोबाइल नंबर के बजाय ई-मेल का उपयोग किया जा सकता है। दूरसंचार विभाग ने कहा, ''...भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए वैकल्पिक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर ग्राहक के हस्ताक्षर प्राप्त करने की आवश्यकता को अनिवार्य नहीं बनाने का निर्णय किया गया है।'' आदेश में कहा गया है कि यदि वैकल्पिक नंबर पर ओटीपी भेजना संभव नहीं है, तो दूरसंचार परिचालक विदेशी नागरिकों के ई-मेल पर ओटीपी भेज सकता है। दूरसंचार विभाग ने कहा कि छूट केवल भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए होगी।

अमेजन ने अप्रैल-जून तिमाही में 13.5 अरब अमेरिकी डॉलर की कमाई की

सिएटल (अमेरिका)@एजेंसी। प्रौद्योगिकी कंपनी अमेजन ने अप्रैल-जून तिमाही में 13.5 अरब अमेरिकी डॉलर की कमाई की। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सिएटल स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी की कमाई के यह आंकड़े फैक्टसेट द्वारा अनुमानित 10.99 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। समीक्षाधीन तिमाही में प्रति शेयर आय 1.26 अमेरिकी डॉलर रही, जो विश्लेषकों की 1.03 अमेरिकी डॉलर की अपेक्षा से अधिक है। कंपनी ने 10 प्रतिशत अधिक 148 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित किया। हालांकि, यह विश्लेषकों की 148.67 अरब अमेरिकी डॉलर की अपेक्षाओं से थोड़ा कम है। इस बीच, कंपनी के मुख्य ई-वाणिज्य व्यवसाय के राजस्व में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके विज्ञापन व्यवसाय से बिक्री में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अब ड्रोन से कूरियर डिलीवर करेगी DTDC

नई दिल्ली@एजेंसी

देश की प्रमुख कूरियर सेवा कंपनी डीटीडीसी एक्सप्रेस लि. ने ड्रोन से कूरियर पहुंचाने की सेवा शुरू की है। कंपनी ने इसके लिए ड्रोन सेवा प्रदाता कंपनी स्काई एयर मोबिलिटी के साथ साझेदारी की है।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने अपने 35वें स्थापना वर्ष के मौके पर ड्रोन से पहली डिलिवरी गुरुग्राम में बिलासपुर से सेक्टर 92 में की। इसके तहत 7.5 किमीमीटर की दूरी को केवल तीन से चार मिनट में तय किया गया। आमतौर पर सड़क मार्ग से कूरियर पहुंचाने में 15 मिनट तक लगते हैं। कंपनी ने कहा कि उसका लक्ष्य सालाना लगभग 15.5 करोड़ पार्सल प्रबंधन को और अधिक प्रभावी व कुशल बनाना है।

डीटीडीसी एक्सप्रेस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अभिषेक चक्रवर्ती ने कहा, हम डीटीडीसी के सफर के 35वें वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। स्काई एयर के साथ रणनीतिक साझेदारी के साथ यह एक नए सफर की शुरुआत है।

स्काई एयर के संस्थापक और सीईओ अंकित कुमार ने कहा कि यह एक बड़ी और व्यापक शुरुआत है, जिसमें भविष्य में अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे।

'फूड प्रोडक्ट्स में नमक, चीनी की जानकारी देने के एफएसएसएआई के फैसले का स्वागत'

नई दिल्ली@एजेंसी

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने शुक्रवार को पैकेट वाले खाद्य पदार्थों पर नमक, चीनी, वसा के बारे में मोटे अक्षरों में जानकारी देने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए एफएसएसएआई का स्वागत किया।

एसजेएम ने कहा कि इससे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर और अन्य बीमारियों में काफी कमी आएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने हाल में पैकेट वाले खाद्य पदार्थों पर पोषण संबंधी जानकारी देने के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। इसमें खाद्य उत्पादों के पैकेट पर नमक, चीनी और संतृप्त वसा की मात्रा की बड़े और मोटे अक्षरों में जानकारी देने की बात कही गई है।

एसजेएम के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन ने एक बयान में कहा कि लोगों में पैकेट वाले खाद्य पदार्थों, खासकर 'अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद' की हानिकारक सामग्री के बारे में जागरूकता की कमी है। ऐसे में लोग अनजाने में ही इन हानिकारक खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं।

महाजन ने कहा, ऐसी स्थिति में यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को बताए कि कौन से खाद्य उत्पाद खाने के लिए सुरक्षित हैं और कौन से नहीं। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ की निर्धारित सीमा से अधिक चीनी, नमक या संतृप्त वसा वाले खाद्य उत्पादों पर यदि ऐसी चेतावनी प्रदर्शित की जाती है, तो उपभोक्ता सजग हो सकेंगे और वे अपने भोजन के बारे में अधिक जानकारीपरक विकल्प चुन सकेंगे।

झंडेवालाज फूड्स लिमिटेड
(CIN: L15209RJ2006PLC022941)
पंजीकृत कार्यालय: बी-70, पहली मंजिल, उपासना हाउस, जनता स्टोर, बापू नगर, जयपुर - 302015, राजस्थान, (भारत)।
दुरभाष: 0141-2703308 ईमेल: acc.jfpl@gmail.com वेबसाइट: www.namans.co.in

18 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

यह सूचना दी जाती है कि झंडेवालाज फूड्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 18 वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 28 अगस्त 2024 को सुबह 9.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम से एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में, यथा संशोधित, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") परिपत्र दिनांक 05.05.2022 पठित परिपत्र दिनांक 13.01.2021 और 05.05.2020 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, जैसा कि संशोधित किया गया है। के अनुपालन मे, आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना के साथ 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट 02/08/2024 को उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) या संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट www.namans.co.in , स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

अधिनियम की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों, संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 और सेबी परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, कट-ऑफ तिथि, यानी बुधवार, 21 अगस्त 2024 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से 18 वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश 18वीं एजीएम की सूचना में निहित हैं।

इस संबंध में, सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि:

i. रिमोट ई-वोटिंग रविवार 25 अगस्त 2024 (सुबह 10 बजे) से शुरू होगी और मंगलवार 27 अगस्त 2024 (शाम 5 बजे) को समाप्त होगी।
ii. ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तिथि बुधवार, 21 अगस्त 2024 होगी।
iii. कोई भी व्यक्ति जो नोटिस के प्रेषण के बाद, कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 21 अगस्त 2024 को शेयर रखता है, वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए, एजीएम के नोटिस में उल्लिखित निर्देशों का पालन कर सकता है या वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।
iv. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति मंगलवार 27 अगस्त 2024 को शाम 5.00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी।
v. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला था और अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश 18वीं एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।
vi. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम में फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
vii. एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि के अनुसार दर्ज है, केवल वही, एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई- वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
viii. इस संबंध में संचार/प्रश्न हमारे आरटीए, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को इसकी ईमेल आईडी investor@bigshareonline.com पर संबोधित किए जाएंगे।

कृपया समय पर संचार प्राप्त करने के लिए अपनी अपडेट की गई ईमेल आईडी को कंपनी/अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत रखें।

झंडेवालाज फूड्स लिमिटेड के लिए
Sd/-
राकेश बी कुलवाल
डीन: 00615150
प्रबंध निदेशक

दिनांक: 02/08/2024
जगह: जयपुर

Monsoon Watch

FLASH FLOOD WARNING

Moderate flash flood risk over Jaisalmer, Barmer, Jalore & Jodhpur districts of West Rajasthan

Moderate flash flood risk likely over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Jharkhand

Moderate flash flood risk likely over Assam & Meghalaya and SHWB & Sikkim

Rainfall Deficiency June 1-Aug 2/Aug1-Aug2

East & NE	(-16.1%)/79.4
Northwest	(-11.7%) /115.6
Central	(18.1%)/+47.3
South Peninsula	(26.8%)/+28.7
Country as a whole	(4.4%)/+68.5

CURRENT WEATHER & FORECAST

Under the influence of low-pressure area, isolated extremely heavy rainfall likely over Madhya Maharashtra, East Madhya Pradesh, West Madhya Pradesh on Aug 3-4; Gujarat region, Konkan & Goa; East Rajasthan on August 4

NTPC-NPCIL JV Likely to Invest ₹50,400 cr in 2,800 MW N-Plant

NTPC also looks to list its green arm in November targeting a 10% dilution of its stake

Our Bureau

New Delhi: NTPC Ltd and Nuclear Power Corporation of India are likely to invest around ₹50,400 crore for 2,800 MW Mahi-Banswara nuclear power plant, which is to be jointly developed by the two state-owned companies.

The power generator expects the tendering process for the nuclear power project to start in the current financial year, people in the know said.

A proposal for transfer of the nuclear units to joint venture Anushakti Vidhyut Nigam Ltd from parent NPCIL is likely to go to the Cabinet this month. The company will, however, not be involved anymore in the 1,400 MW Chutka Madhya Pradesh Atomic Power Project, which was also to be jointly developed with NPCIL, the person said.

For the power major, the Mahi-Banswara project would be an experience to carry forward its nuclear energy plans on a standalone basis, the person said.

The company is bullish on new technologies and is looking for technology partners in the small reactors segment.

GREEN IPO

The company is also looking to list its green arm in November targeting a 10% dilution of its stake, the person said. In November, NTPC Green Energy Ltd (NGEL) is likely to have a total installed capacity of 4,000 MW, another 8,000 MW under construction and 8,000 MW more in various stages of planning.

NGEL will drive India's largest power producer's ambitious clean energy programmes. The company will have subsidiaries and joint ventures to carry out the projects. The power generator's subsidiary will be the flagbearer of its aim to add 60 GW renewable energy capacity by 2032. It is also looking to develop pumped hydro storage and green hydrogen and ammonia manufacturing projects.

COAL PROCUREMENT

For the first time NTPC has issued an order to procure coal to the tune of 1 million tonnes from the commercial coal mines. These mines were opened for the private sector in 2020. This tender, which was placed last month, is on fuel transported to plant basis and the cost is projected to be lower than import, the person added.

Zerodha, Wistron Penalised for Company Law Breach

Banikinkar Pattanayak

New Delhi: The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has penalised Zerodha Asset Management and Wistron Infocomm Manufacturing (India) for their failure to appoint key executives on time in breach of the company law provisions.

In an order reviewed by **ET**, the Registrar of Companies (RoC) for Karnataka has imposed penalties totalling almost ₹24 lakh on Zerodha, its director Nithin Kamath, chief executive Vishal Virendra Jain and four others, citing the absence of a chief financial officer in the company for 459 days until the appointment of Chintan Vasantlal Bhatt on March 24, 2023.

In another order seen by ET, the same RoC imposed a total penalty of ₹11.89 lakh on Wistron, its then chief executive Gururaj Ayekawadi and three others for failure to appoint a company secretary on time.

RoC functions under the MCA.

SUO MOTU ACTION

Both the orders were based on 'suo motu applications' for settlement filed by the companies, admitting to violation. Also, while the two cases are unrelated, both the companies violated Section 203 of the Companies Act that deals with the appointment of key personnel.

Zerodha filed its application on January 9 this year for the violation of rules between December 20, 2021, and March 23, 2023. Wistron, one of the contract manufacturers of Apple Inc, filed its application on January 17 for non-compliance for a few months in 2018 and again in 2020. Wistron's noncompliance predates its acquisition by Tata Electronics in late 2023. Industry watchers said a growing number of companies are approaching the authorities themselves to pay up for minor breaches of rules to keep their records clean.

Also, various RoCs have in recent months hardened their crackdown on contraventions of rules by companies even as the government has reduced the compliance burden of India Inc, they added.

THE PENALTIES

In the case of Zerodha, the penalty on the company is ₹5 lakh while Kamath is liable to pay ₹4.08 lakh, director Rajanna Bhuvanesh ₹5 lakh, and four others between ₹1.5 lakh and ₹3.45 lakh each. In Wistron's case, the company is subject to a penalty of ₹5 lakh, while its former chief executive Ayekawadi must cough up ₹2.24 lakh and three directors ₹1.55 lakh each.

The RoC in its orders pointed out that Zerodha and Wistron do not fall under the definition of small companies. "Therefore, the provisions of imposing lesser penalty as per the Section 446B of the Act shall not be applicable," the orders read.

FM to Address RBI Board on Aug 10

New Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman is scheduled to address the Reserve Bank of India's central board on August 10 and highlight key points of the Budget FY25, including the fiscal consolidation roadmap.

The post-budget meeting has been scheduled for August 10 where the finance minister will address the board members and talk about announcements made in the budget 2024-25 that strike a fine balance between growth, employment, and fiscal prudence, sources said. It is customary for the finance minister to address the RBI board after the budget. Unveiling the Budget on July 23 in the Lok Sabha, Sitharaman said the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at ₹32.07 lakh crore and ₹48.21 lakh crore, respectively, for 2024-25. The net tax receipts are estimated at ₹25.83 lakh crore, she said, adding that the fiscal deficit is estimated at 4.9 per cent of the GDP. —**PTI**

FOLLOWING FM'S ANNOUNCEMENT IN BUDGET...

Task Force in Works to Lay out Road map for Cos to Hire Interns

Officials from Edu Min, DPIIT to be part of the task force; total central allocation pegged at ₹63k cr

Yogima Seth

New Delhi: The government is likely to set up a task force under the corporate affairs ministry to firm up the contours of the proposed internship scheme and lay out a roadmap for top 500 companies to hire interns, a senior official told **ET**.

"The task force, which will have officials from the Ministry of Education and Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) among others, will undertake mapping of industry around colleges and nudge companies there to hire interns in the catchment area," said the official who is aware of the deliberations.

Finance minister Nirmala Sitharaman in the Union Budget 2024-25 said the government will provide one-year internship opportunities in 500 top companies to 10 million youth in five years.

The scheme is likely to be rolled out towards the later part of this fiscal year, the official said.

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) will soon move a draft scheme for approval by the expenditure finance committee (EFC), following which it will go to the Union Cabinet, the person said.

Under the scheme, each intern will get a monthly allowance of ₹5,000 plus a one-time assistance of ₹6,000. Out of this, the government will bear ₹54,000 towards monthly allowance and the one-time assistance of ₹6,000, totalling ₹60,000 a year per intern. Companies will need to bear the training cost and 10% of the monthly allowance (₹6,000 in a year) from their corporate social responsibility (CSR) funds.

"They (interns) will gain exposure for 12 months to real-life business environments, varied professions and employment opportunities," Sitharaman said in her budget speech.

Under phase I of the scheme, which will see enrolments in the first two years and expenditure spread over three years, the plan is to provide internship to three million candidates with an outlay of ₹19,000 crore.

NCLT Approved Record 269 Resolution Plans in FY24

Mumbai: The National Company Law Tribunal (NCLT) approved a record 269 resolution plans under the insolvency law in 2023-24, which is 42% higher than the year-ago period, a report by Crisil Ratings said. Of the 269 cases, 88% are from the backlog of earlier years' admissions. This has been driven by greater investor interest in turnaround of stressed assets as seen in the resolution plan submissions. Appointment of new NCLT members has also aided in higher number of resolution cases. However, the moderation in recovery rates and stretched timelines played spoilsport. FY2023-24 saw resolution plans with recovery rate of 27% of admitted claims, lower than 36% realised in FY23. —**PTI**

Record 7.28 cr ITRs Filed till July 31, 72% Opted for New Tax Regime

Our Bureau

New Delhi: A record 7.28 crore Income tax returns (ITRs) were filed till July 31 for the assessment year 2024-25, 7.5% higher against the same period last year, official data released Friday revealed.

Of the total returns filed, 5.27 crore have been filed in the new tax regime, which means that 72% of the taxpayers who filed tax returns, switched to the new tax regime. Now only 28% of taxpayers remain in the old tax regime.

A total 6.77 crore ITRs were filed for the assessment year 2023-24 till July 31, 2023 out of which 2.01 crore tax payers have opted for the new tax regime. The last date for filing return was July 31.

"The department also received 58.57 lakh ITRs from first-time filers, a fair indication of the widening of the tax base," the Central Board of direct taxes (CBDT) said in a statement Friday.

Over 69.92 lakh ITRs were filed on a single day on July 31.

Out of the 7.28 crore ITRs filed for AY 2024-25, 45.77 % of ITRs are ITR-1 (3.34 crore), 14.93% are ITR-2 (1.09 crore), 12.5% are ITR-3 (91.10 lakh), 25.77 % are ITR-4 (1.88 crore) and 1.03% are ITR-5 to ITR-7 (7.48 lakh).

Till date over 6.21 crore ITRs have been e-verified and more than 2.69 crore ITRs for the AY 2024-2025 have been processed till July 31, 2024.

"The e-filing helpdesk team has handled approximately 10.64 lakh queries from taxpayers during the year up to July 31, supporting the taxpayers proactively during the peak filing period," it said.

Uneven Rainfall may Flare up Food Inflation: Experts

Suhani Sirohi and Samiha Jha

New Delhi: After a deficient June, monsoons have picked up pace in India, recording above-normal cumulative rainfall for July, with this unevenness is expected to flare up food inflation, said economists.

Food inflation rose to a six-month high of 9.36% in June.

"Inflation expectations for crops should be more subdued on account of rainfall progress," said Madan Sabnavis, chief economist at Bank of Baroda, highlighting that the progress from now on till the harvest (in September) will influence sentiment, as any news of excess or deficit rainfall in any specific division which covers production of any crop can have an inflationary signal. The spatial distribution of rainfall was uneven this season, with Southern and Central India receiving excess rain, while 10 met divisions saw a double-digit deficit. "The risk of food inflation continues to remain elevated as key agrarian states in northern India and the Eastern Gangetic plains continue to experience deficit rainfall", said Rajani Sinha, chief economist, CareEdge. Compared to July 2022, the area sown has actually decreased by 2.4%, primarily due to poor sowing of pulses.

"Going forward, even though a high base last year is going to pull headline inflation down towards 4% in Q3, there are upside risks to food inflation due to an uneven monsoon even as sowing of key summer crops are tracking better than last year," Goldman Sachs said in a report Friday.

CORE ISSUE

Experts also anticipate an upward trend in core inflation.

"Core inflation has started rising as companies try to cover higher input costs. With growth expected to be above 7% this year, the demand-pull forces would also come into action. Therefore, we can expect core inflation to move upwards towards 4% from the present level of 3%," noted Sabnavis.

Gupta said core inflation will show flattish movement, before it rises again at the end of the year, citing low base effect and consumption recovery as the reason.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

Asset Recovery Branch; 101-110, First floor, Anukampa Tower, Church Road, Jaipur (Rajasthan)-302001

WITHDRAWAL OF POSSESSION NOTICE

Possession Notice Dated 20.01.2024 which was Published in this newspaper on 25.01.2024 of Borrower M/s Swastik Coppers Pvt. Ltd. property- Residential Plot No. 8 -A at Sagar Colony, Falna, Pali, admeasuring 2679.00 Sq. Ft. in the name of Mrs Indra Jain, Bounded as: East: Property of Shashi Jain, West: 10' Wide Road, North: Remaining Part of Plot No 8, South: 12.00 Ft Road. Withdrawn due to unavoidable reasons.

Authorised Officer, Union Bank of Bank

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

Tender No : Re-E-Tender No 26/2024-25/SE/PHC/CHN

AMRUT-2.0 Water Supply improvements to Kaloor Zone-Laying Distribution mains from the OHSR at Kaloor-General Civil Work-1- From OHSR to Kaloor Junction and Palarivattom. **EMD :** Rs. 500000 **Tender fee :** Rs. 19518. **Last Date for submitting Tender :** 16-08-2024 03:00:pm **Phone :** 0484-2360645 Website : www.kwa.kerala.gov.in & www.etenders.kerala.gov.in.

KWA-JB-GL-6-330-2024-25 **Superintending Engineer, PH Circle, Kochi**

एन सी एल NCL Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A Subsidiary of Coal India Limited)

Tender Notice

"All the tenders issued by CIL and its Subsidiaries for procurement of Goods, works and Services are available on website of Coal India Limited **www.coalindia.in**/respective subsidiary Company, CIL e-procurement portal **https://coalindiatenders.nic.in** & central public procurement portal **https://eprocure.gov.in.** In addition, procurement is also done through GeM Portal **https://gem.gov.in** ." **(R-33)**

THE NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD.
Regional Office: II floor, Nehru Place, Tonk Road, Jaipur-302015, Tel.: 0141-2745701-2745775

E-Tender Notice

Requirement of Commercial Space on Lease for Udaipur Office

The New India Assurance Company Limited, Jaipur Regional Office requires Commercial Space on lease measuring arround 3000-3500 Sq. ft. (Carpet Area) for its Udaipur office.

E-Tenders are invited from interested bidders/parties for their bids/offers.

Tender documents along with terms and conditions can be downloaded from the Company's website **https://newindia.co.in**.

Entire tender document for the premises is to be submitted online and in 2 separate parts i.e. 1- Technical Bid and 2- Price Bid on our website **www.tenderwizard.com/NIAEPROC**.

Bids are to be submitted online only on or before 12th August, 2024 up to 5.00 PM. Bidders are requested to visit the aforementioned website for any corrigendum addendum notice.

The Company reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning reason(s) thereof.

(B.C. Sethi)
Chief Regional Manager

JHANDEWALAS FOODS LIMITED
(CIN: L15209RJ2006PLC022941)
Registered office: B-70, 1st Floor, Upasana House, Janta store, Bapu Nagar, Jaipur - 302015, Rajasthan, (India).
Tel: 0141-2703308, E-mail: acc.jfpl@gmail.com, Website: www.namans.co.in

NOTICE OF THE 18TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Jhandewalas Foods Limited ('the Company') will be held on Wednesday, 28th August, 2024 at 09.30 A.M through video conferencing or Other Audio Visual Means ('OAVM') facility without physical presence of the members at a common venue, in compliance with provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and rules thereof, as amended, Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular dated 05th May 2022 read with circulars dated 13.01.2021 and 05.05.2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.

The Annual Report including the financial statements for the financial year ended 31st March 2024 along with Notice of the AGM has been dispatched on 02/08/2024 to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or with the respective Depository Participants. Members may take a note that the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 will also be available on the Company's website www.namans.co.in, website of the stock Exchange i.e. www.bseindia.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com.

Pursuant to provisions of section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circular dated 9th December, 2020, members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e., Wednesday, 21st August 2024, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 18th AGM through e-voting platform. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 18th AGM.

In this regard, the members are hereby further notified that:

i. Remote e-voting shall commence from Sunday, 25th August 2024 (10.00 A.M.) and shall end on Tuesday, 27th August 2024 (05.00 P.M.).
ii. Cut-off date for the purpose of e-voting shall be Wednesday, 21st August 2024.
iii. Any person who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, 21st August 2024, may follow the same instructions as mentioned in notice of AGM for remote e-Voting or sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.
iv. Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on Tuesday, 27th August 2024.
v. Members present at the meeting through VC/OAVM and who had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of 18th AGM.
vi. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility, but shall not be allowed to cast their votes again at the AGM.
vii. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail of the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM.
viii. Communications/queries in this respect shall be addressed to our RTA, Bigshare Services Private Limited to its email id investor@bigshareonline.com.

Please keep your most updated email id registered with the company/your Depository Participant to receive timely communications.

For JHANDEWALAS FOODS LIMITED
Sd/-
Raakesh B Kulwal
DIN: 00615150
Managing Director

Date: 02 August 2024
Place: Jaipur

GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking)
ITUWTSA

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF GAIL (INDIA) LIMITED

In line with the SEBI and MCA Circulars, the Notice of 40th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24, has been sent to the Members of the Company through electronic mode whose e-mail ID(s) are registered with the Depository Participant (DP) or R&TA. The same is also hosted on the website(s) of the Company **(www.gailonline.com)**, Stock Exchanges i.e. BSE Limited **(www.bseindia.com)**, National Stock Exchange of India Limited **(www.nseindia.com)** and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (agency for providing the Remote e-Voting facility) **(www.evotingindia.com)**.

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations 2015, Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on all resolutions set forth in the Notice convening the 40th AGM using electronic voting system **('Remote e-voting')**. The Company has engaged the services of Depository viz. **Central Depository Services (India) Limited ('CDSL')** to provide the remote e-voting facility. The remote e-voting period commences on **Saturday, 24th August, 2024 (9:00 am) (IST) and ends on Tuesday, 27th August, 2024 (5:00 pm) (IST)**. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for remote e-voting thereafter and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person whose name is registered as a member in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on **cut-off date i.e. Wednesday, 21st August, 2024** shall be entitled to avail the facility of a) remote e-voting; b) participation at the AGM through VC/OAVM; and c) vote through e-voting mode available during the AGM.

The members who have casted their vote by remote e-voting mode may also attend the AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote during the AGM. Once a vote on a resolution is submitted by the member through remote e-voting or e-voting, the member shall not be allowed to change it. The remote e-voting facility is available to the members as on the cut-off date at **www.evotingindia.com**. Only those members, who would be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

Members are requested to refer to instructions for remote e-voting which forms a part of AGM Notice. If you have any queries or issues regarding attending the AGM &/or casting vote through remote e-voting or e-voting mode(s) using the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at **www.evotingindia.com**, under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact at toll free no. 1800 22 55 33. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Shri Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call at aforementioned toll free number. Alternatively, the members may contact our R&TA at admin@mcsregistrars.com or Mr. Ajay Dalal, Sr. Manager (Admin), MCS STA at **91-11-41406149-52** (Address: MCS Share Transfer Agent Limited, **Unit: GAIL (India) Limited**, 1st Floor, F-65, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020).

If a person is already registered with CDSL/NSDL for e-voting then existing login ID and password to be used for remote e-voting or e-voting. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds share as on cut-off date may obtain the login id and password by sending request along with their shareholding details to **shareholders@gail.co.in** or **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.

In terms of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing one-way live webcast of the proceedings of the AGM for the shareholders on **Wednesday, 28th August, 2024 from 11:30 a.m.** onwards till conclusion of the AGM. You may access the same at GAIL's website **(www.gailonline.com)**.

Members holding shares in physical mode are requested to get their holdings converted into dematerialised mode. To enable the Company to better serve its members it is requested that those members who wish to avail the National Automated Clearing House (NACH) facility i.e. direct credit of dividend amount in the bank account are requested to update their bank details with their Depository (DP) (if shares are held in electronic mode) or R&TA/Company (if shares are held in physical mode).

Member(s) who have not yet encashed their Dividend Warrant(s) may approach the R&TA/Company for issuance of demand draft(s) upon completion of necessary formalities, at least 3 weeks before the due date for transfer to IEPF. Member(s) may visit **'Investor Zone'** section at Company's website for further reference. To facilitate the member(s) to register their request/complaint, if any, designated e-mail ID of the R&TA and Company is **admin@mcsregistrars.com** and **shareholders@gail.co.in** respectively.

For GAIL (India) Limited
Sd/-
(Mahesh Kumar Agarwal)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 03.08.2024
E-mail: shareholders@gail.co.in

Regd. Office: 16, Bhikaiji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi – 110066
Corporate Identification Number: L40200DL1984GOI018976
Phone: 011-26182955, Fax: 011-26185941

www.gailonline.com #EnergizingPossibilities Follow us on

HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
CIN: L35301KA1963GOI001622

Regd. Office: 15/1, Cubbon Road, Bengaluru-560001
Tel.: 080-22320001 E-mail: investors@hal-india.co.in
Website: www.hal-india.co.in

NOTICE OF THE 61ST ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 61st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Wednesday, August 28, 2024 at 3.00 P.M. (IST)** through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business set out in the Notice of the AGM ('Notice'), in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013, Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent Circulars issued from time to time and General Circular No 09/2023 dated September 25, 2023 and relevant Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) from time to time, (hereinafter collectively referred to as "Circulars").

In compliance with the above referred Circulars, electronic copies of the Notice of the 61st AGM and Annual Report 2023-24 have been sent to all the members whose E-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at www.hal-india.co.in/Investors, Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("the RTA") at https://evoting.kfintech.com and Stock Exchange i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The dispatch of Notice of the AGM through E-mails has been completed on 02.08.2024.

1. Manner of casting vote through e-voting:

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with applicable rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, members are provided with the facility to cast their vote by electronic means on all the resolutions set out in the Notice. In this connection, Members are hereby informed that:

i) Company has engaged KFin Technologies Ltd. ("KFintech") as the Agency to provide e-voting facility.
ii) M/s DPSP & Associates, Company Secretaries, Bengaluru has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
iii) The remote e-voting period will commence on Saturday, August 24, 2024 (9.00 A.M. IST) and ends on Tuesday, August 27, 2024 (5.00 P.M. IST).
iv) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, i.e. Wednesday, August 21, 2024, will only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in AGM.
v) Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of Notice of the 61st AGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. August 21, 2024 may obtain the login ID and password by following the procedure as mentioned in the Notice for the AGM or send a request to evoting@kfintech.com or einward.ris@kfintech.com.
vi) Voting through remote e-voting will not be allowed beyond 5.00 P.M. (IST) on Tuesday, August 27, 2024. The remote e-voting module will be disabled by KFintech for voting thereafter.
vii) The facility for voting will also be made available during the AGM and those members who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM.
viii) The members who cast their votes by remote e-voting prior to the date of AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.
ix) For e-voting instructions, members may go through the instructions in the Notice for 61st AGM. In case of any queries / grievances in connection with e-voting, members may refer the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) available at https://evoting.kfintech.com or may contact to Ms B Swati Reddy, KFin Technologies Ltd, at Toll free number 1800 309 4001 or at e-mail Id: einward.ris@kfintech.com.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made there under, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 22, 2024 to August 28, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the 61st AGM.

Members who have not registered their e-mail addresses and mobile number so far or who want to update their e-mail address and mobile number, are requested to approach their respective DP for shares held in electronic mode and in respect of shares held in physical form by writing to Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Ltd at einward.ris@kfintech.com by mentioning their folio number, for receiving all communications electronically.

2. Record Date for Final Dividend:

Members may note that the Board of Directors at their meeting held on June 26, 2024 has recommended a final dividend of Rs. 13/- per share. The final dividend, subject to approval of Members, will be paid to the Members, whose names appear in the Register of Members, as on the Record Date, i.e. Wednesday, August 21, 2024 through permissible modes.

3. Tax on Dividend:

i) Members may note that the Income Tax Act, 1961 (Act), as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a Company after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Members. The Company shall therefore be required to deduct Tax at Source (TDS) at applicable rates, at the time of making payment of the final dividend.
ii) Since the TDS / withholding tax rates are different for resident and non-resident Members, if there is a change in your residential status, as per the provisions of the Act, you are requested to get your residential status updated before Record Date in your demat account or the physical folio, as applicable.
iii) In order to enable us to determine the appropriate TDS rate, as applicable, Members are requested to submit the tax related documents in accordance with the provisions of the Act on or before **August 22, 2024** at einward.ris@kfintech.com.
iv) Tax Exemption Forms are available at https://ris.kfintech.com/form15/default.aspx .

By order of the Board of Directors
For Hindustan Aeronautics Ltd.
Sd/-
(Shailesh Bansal)
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Bengaluru
Date: 02.08.2024